

‘अमेरिका, उन देशों पर जो रूस से ऑयल खरीदना जारी रखेंगे, 500 प्रतिशत टैरिफ लगायेगा’

अमेरिका के सिनेट में प्रस्तुत इस विधेयक, जिसे दोनों पार्टियों, रिपब्लिकन व डेमोक्रेटिक पार्टी, का आंशिक समर्थन प्राप्त है, का भारत पर व्यापक प्रभाव पड़ेगा

-सुकमार साह-

-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्लूरो-

विधेयक नियमित विधेयक, जिसमें एक नया बिल (सेंटरिंग रिशियर एक्ट ऑफ 2025, एस.1241) यात्रा है कि जो ऑयल, जिनमें भारत भी शामिल है, से रूस से तेल, गैस, पैट्रोकेमिकल या यूरोपियन की खरीद जारी रखेंगे, उनके उत्पादों पर अमेरिका 500 प्रतिशत टैरिफ (आराम शुल्क) लगा सकता है।

यह विधेयक सोनोटर लिंडेसे ग्राहम और चिर्च ब्लूरो द्वारा पेश किया गया है और इसे 80 से पूर्वीक सेनेटों का समर्थन प्राप्त है। डॉनल्ड ट्रम्प ने न केवल इस विधेयक के कार्रवाय में पारित होने का समर्थन किया है, बल्कि भविष्य के राष्ट्रपतियों को रखने पर दबाव बनाने के लिए एक “टूलबाब्स” देने की वकालत की है, हालांकि उन्होंने इसमें एक प्रैज़िडेंशियल छूट का प्रावधान भी सुनिश्चित किया है, जिससे राष्ट्रपति चाहे तो टैरिफ को निर्लिपित कर सकते हैं।

- रूस ने प्रत्युत्तर में घोटाया है कि भारत जैसे देश पर इस तरह का दबाव बनाना, यूक्रेन में चल रहे शांति प्रयासों को जोखिम में डाल सकता है।
- भारत, अमेरिका का फार्मस्यूटिकल्स, आईटी सर्विसज, ऑटो पार्ट्स तथा जावाहरात नियर्यात करता है। भारत के ये नियर्यात, अमेरिका में बिना किसी रुकावट के पहुंचते हैं। पर, अगर, अमेरिका ने भारत के इस नियर्यात पर 500 प्रतिशत टैरिफ लगाया तो ये आइटम इतने महंगे हो जायेंगे कि अमेरिका में इनकी बढ़िया खत्म सी हो जायेगी।
- अमेरिका अपनी इकोनॉमिक ताकत का उपयोग, भारत की विदेश नीति को प्रभावित करने के लिए काम ले सकता है। अतः भारत ने अब ज्यादा से ज्यादा ऑयल अमेरिका से खरीदना शुरू कर दिया है, जिससे वो अमेरिका की व्यवसायिक धमकी में भी जी सके तथा अमेरिका के समृद्ध मार्केट में दीर्घकालीन एन्ट्री बनाये रख सके।

क्रेमलिन ने घोटाकी दी है कि भारत जैसे प्रमुख खरीदारों पर दबाव

डालने जैसे कदम युक्त हैं कि भारत जैसे देशों पर इस विधेयक को घोटाया है।

विशेषज्ञों का मानना है कि यह 500 प्रतिशत टैरिफ का प्रस्ताव एक गंभीर खत्म है। यह उन देशों को नियाना बनाता है, जो रूस से तेल खरीद जारी रखते हैं, लेकिन यह दंड सोधे उनके तेल व्यापार पर लागू नहीं होता।

भारत के संदर्भ में, यद्यपि वह अपनी कुल जस्तर के कच्चे तेल 40 प्रतिशत आयत रूस से करता है, लेकिन अमेरिका को वह तेल नियर्यात नहीं करता, ऊर्जा क्षेत्र में प्रत्यक्ष टैरिफ लगाने को इर्द गोर प्रयोग नहीं है।

भारत को वीच ऐतिहासिक संबंधों को समर्पित किया गया है इस विशेष सम्बन्ध के लिए आगा के लोगों और सरकार को धन्यवाद दिया।

प्रधानमंत्री ने यह किया कि यह पुरस्कार

दोनों देशों के वीच मित्रता को और गहरा करता है तथा द्विपक्षीय संबंधों को अगे बढ़ाने की उपर नई विदेशी दलालत है। उन्होंने कहा कि उन्हें विवाद है कि आगा की उत्तरी ऐतिहासिक राजकीय आगा दोनों देशों के संबंधों को नई गति

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

प्र.मंत्री मोदी को मिला धाना का सर्वोच्च सम्मान

अबकारा-नवीदिल्ली, 03 जुलाई। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को धाना के सर्वोच्च सम्मान, ‘द ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ चाना’ से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति जॉन महामा ने उन्हें यस सम्मान प्रदान किया। मोदी ने बुधवार को इस सम्मान के लिए आगा के राष्ट्रपति को धन्यवाद दिया और इसे ‘अलंकृत गवर्नर का विषय’ बताया। प्रधानमंत्री ने 140 करोड़ भारतीयों को ओर से पुरस्कार स्वीकार करते हुए इस सम्मान को उन्होंने की आकांक्षाओं, इसकी सांस्कृतिक परंपराओं और विविधता तथा धाना और

बिहार में मतदाता के धार्मिक ध्वनीकरण की राजनीति शुरू हो गई?

भाजपा ने आरजेडी नेता तेजस्वी यादव पर “नमाजवादी” होने का व्यंग्य दागा तथा विपक्ष ने भाजपा पर एनआरसी (नैशनल रजिस्टर फॉर सिटिजन्स) को पीछे के दरवाजे से लाकर लागू करने का आरोप लगाया

-श्रीनंद झा-

-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्लूरो-

नई दिल्ली, 3, जुलाई। चुनाव की ओर बढ़ रहे बिहार में मतदाताओं का धार्मिक आगा पर ध्वनीकरण शुरू हो गया है। जहाँ भाजपा ने राजद (राष्ट्रीय जनता दल) नेता तेजस्वी यादव पर “नमाजवादी” तंज करते हुए इसकी शुरूआत की, वहाँ विपक्षी नेताओं ने एनडीए पर एनआरसी को पिछले दरवाजे से लागू करने की कोशिश का आरोप लगाया है।

तेजस्वी यादव द्वारा यह कहे जाने पर किंवदक एकट को करवे में फैक दिया जाएगा कि बिहार में लागू नहीं होगा।

प्रधानमंत्री ने कहा कि यह पुरस्कार

दोनों देशों के वीच मित्रता को और गहरा

करता है तथा द्विपक्षीय संबंधों को अगे बढ़ाने की मांस्त्रा

है। उन्होंने कहा कि उन्हें विवाद है कि आगा की उत्तरी ऐतिहासिक राजकीय आगा दोनों देशों के संबंधों को नई गति

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

-तेजस्वी यादव का दावा है कि वक्त एकट को कुड़े की टोकरी में फैक दिया जायेगा तथा बिहार में कभी लागू नहीं होगा, पर, संवित पात्रा ने कहा कि महागठबंधन बिहार में “शरिया कानून” लागू करना चाहता है।

प.बंगल की मु.मंत्री ने कहा कि बिहार में स्पैशल इन्टैन्सिव रिवीजन (एसआईआर) को लागू करने का असली टारगेट तो प.बंगल है। बंगल के ग्रामीण क्षेत्रों के मतदाताओं के नाम मिटा दिए जाएंगे तथा उनकी जगह, बिहार, यू.पी., राजस्थान, हरियाणा आदि के मतदाताओं से भर दी जायेगी।

यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि मु.मंत्री नीतीश कुमार ने 2019 में बिहार में बारे-में कहा था, “कहाँ का एनआरसी। बिल्कुल लागू नहीं होगा।” देखना है, अब उनका रुख क्या रहता है।

इस बीच, चुनाव आयोग द्वारा निर्णय को लेकर एक बड़ा विवाद बिहार की मतदाता सूचीयों से विषेष उभरता दिख रहा है। इस प्रक्रिया के गहराने पुनर्नीर्णयण (स्पैशल इन्टैन्सिव) तहत, 2003 के बाद मतदाता सूचीयों में रिलीज़-ए-एसआईआर (एसआईआर) करने के (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

‘एस.आई.आर. लागू हुआ तो बिहार के 20% मतदाता अपना “वोटिंग” का अधिकार खो देंगे’

इंडिया ब्लॉक ने चुनाव आयोग से कहा कि बिहार के “माइग्रेंट वर्कर” (घुमंतु मजदूर) 1 महीने में अपने आप को नये तरीके से मतदाता के रूप में “रजिस्टर” नहीं कर पायेंगे

-श्रीनंद झा -

-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्लूरो-

नई दिल्ली, 3, जुलाई। इंडिया गठबंधन के नेताओं ने चुनाव आयोग पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि आयोग द्वारा राजद की मतदाता सूची को संवेदन इन्टैन्सिव रिवीजन (एस.आई.आर.) करने के फैसले से विषेष उत्तरी रेसिवर्स के वीच मित्रता को अपने आप से बदल दिया गया है।

कांग्रेस की ओर से अधिकरण मनु सिंधिया ने पार्टी का पक्ष रखा और कहा कि वीच ऐतिहासिक राजकीय आयोग के लिए एक बड़ा विवाद है।

बुधवार को चुनाव आयोग के अधिकारियों के साथ विषेष उत्तरी रेसिवर्स की वीच ऐतिहासिक राजकीय आयोग के लिए एक बड़ा विवाद है।

बुधवार को चुनाव आयोग के अधिकारियों के साथ विषेष उत्तरी रेसिवर्स की वीच ऐतिहासिक राजकीय आयोग के लिए एक बड़ा विवाद है।

किंवदक दिल्ली के 20 सदस्यों का सिंह बैठक में शामिल नहीं हो सके और प्रतिनिधिमंडल निवाचन सदन पूर्ण हुआ।

उन्हें लगाने वाले तंजे तंजे बदल दिये गए हैं।

राजद संसद मनोज कुमार जा और अलोकप्रतिक बदल दिये गए हैं।

कांग्रेस की ओर से विषेष उत्तरी रेसिवर्स ने चुनाव आयोग के लिए एक बड़ा विवाद है।

कांग्रेस की ओर से विषेष उत्तरी रेसिवर्स ने चुनाव आयोग के लिए एक बड़ा विवाद है।

कांग्रेस की ओर से विषेष उत्तरी रेसिवर्स ने चुनाव आयोग के लिए एक बड़ा

